गरीबों को लाभ दिलाना

18. श्री ललित कुमार यादव-- क्या मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि गरीबों अत्यन्त पिछड़े एवं पिछड़ा लोगों के लिए लाभार्थ पीला कार्ड बनाने एवं वितरण करने का निर्णय वर्ष 2008-09 में सरकार द्वारा लिया गया है;

(2) क्या यह बात सही है कि राज्य के दरभंगा जिला सहित 38 जिलों में लाल कार्ड एवं पीला कार्ड उपभोक्ताओं को अबतक नहीं दिया गया है जिससे आम गरीब जनता सुविधा पाने में मुहताज हैं;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार अविलम्ब लाल कार्ड, पीला कार्ड का वितरण कर गरीबों को लाभ दिलाने का विचार रखती है?

अनाज का उठाव

19. श्री मंजीत कुमार सिंह--क्या मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि समस्तीपुर, वैशाली, सीतामढ़ी, शिवहर, पश्चिम चम्पारण, मधेपुरा, पूर्णियां, कटिहार, लखीसराय, पटना, रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, अरवल, जहानाबाद, मधुबनी, नवादा, नालन्दा, सुपौल, किशनगंज, छपरा, सिवान के जन-वितरण प्रणाली के दुकानदारों ने बी०पी०एल० परिवार के कोटे के लिए अनाज उठाव हेतु सितम्बर, 2010 में राज्य खाद्य निगम को बैंक ड्राफ्ट द्वारा राशि जमा किया गया था, यदि हां, तो अनाज का उठाव अबतक नहीं होने का क्या औचित्य है?

नवीकृत करना

20. श्री आलोक रंजन-- क्या मंत्री, नगर विकास एवं आवास विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह बात सही है कि जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकृत मिशन हेतु 900 करोड़ का चालू वित्तीय वर्ष में प्रावधान किया गया है, यदि हां, तो सहरसा शहर को नवीकृत करने हेतु सरकार की क्या कार्य योजना है?

राशि का प्रबंध

21. डॉ० अरूण कुमार --क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत वर्ष 2009-10 में कुल 92 करोड़, 23 लाख 74 हजार रुपये व्यय किये गये हैं;

(2) क्या यह बात सही है कि वर्त्तमान वित्तीय वर्ष में इस योजना में केन्द्र से कोई राशि प्राप्त नही हुई है;

(3) यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारत्मक हैं, तो सरकार चालू वित्तीय वर्ष में इस योजना के तहत राशि का प्रबंध किस प्रकार करने का विचार रखती है?

मुआवजा का भुगतान

22. श्रीमती लेशी सिंह-- क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि सरकार द्वारा विगत वर्ष 2009 में लगाई मक्का के फसल में दाना नहीं आने के कारण किसानों के राहत के लिए मुआवजा निर्धारित किया गया था;

(2) क्या यह बात सही है कि पूर्णियां जिला में अभीतक किसानों को मुआवजा का भुगतान नहीं हो सका है;

(3) अगर उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार तत्काल किसानों को मुआवजा का भुगतान दिलाने के लिए विचार रखती है, हां, तो कबतक, नहीं, तो क्यों ?

पैक्सों को संचालित करना

23. श्री प्रदीप कुमार-- क्या मंत्री, सहकारिता विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि पूरे प्रदेश में किसानों के सहायता हेतु वर्ष 2009 में पंचायत स्तर पर पैक्स का चुनाव हुआ है, परन्तु आजतक पैक्स का संचालन शुरू नहीं हो पायी है जिसके कारण किसानों को पैक्स से किसी प्रकार की सुविधा नहीं मिल रही है;

(2) यदि उपर्युक्त खण्ड का उत्तर स्वीकारात्मक है, तो क्या सरकार किसान हित में पैक्सों को सुचारू ढंग से संचालित करवाने का विचार रखती है, यदि हां, तो कबतक, नहीं, तो क्यों?

खाद उपलब्ध कराना

24. श्री विनय कुमार सिंह--क्या मंत्री, कृषि विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य में भदई एवं रबी फसल के लिए वर्ष 2009-10 एवं 2010-11 में क्रमशः 65 लाख टन एवं 60 लाख टन खाद डी०ए०पी०, यूरिया का भारत सरकार से आवंटन मिला है;

(2) क्या यह बात सही है कि खाद का वितरण जिला कृषि पदाधिकारियों एवं सहकारिता विभाग के पैक्स द्वारा किया जा रहा है जो आम किसान को जरूरत के अनुसार नहीं मिल रहा है;

(3) क्या यह बात सही है कि प्रत्येक जिला में आवंटन के अनुसार खाद नहीं मिलने से किसानों को काफी कठिनाई हो रही है;

(4) क्या यह बात सही है कि बिहार का खाद नेपाल के सीमावर्ती जिलों से दुकानदारों द्वारा (डीलर द्वारा) भेजा जा रहा है;

(5) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार आवंटन एवं वितरण की जांच कराने, सही मूल्य पर खाद उपलब्ध कराने का विचार रखती है, नहीं, तो क्यों?

उत्पादन बढ़ाना

25. डॉ० अच्युतानन्द दैनिक समाचार-पत्र के दिनांक 26 मई, 2010 के अंक में प्रकाशित शीर्षक "12 अरब की मछलियां चट कर जाता है बिहार" की ओर आप का ध्यान आकृष्ट करते हुए क्या मंत्री, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य में प्रति वर्ष 4.56 लाख टन मछली की आवश्यकता के विरुद्ध उत्पादन मात्र 3.06 लाख टन है;

(2) क्या यह बात सही है कि राज्य में प्रति वर्ष 1.46 लाख टन मछली राज्य के बाहर से मंगानी पड़ती है, जबकि राज्य की जलवायु जल-जमाव का क्षेत्र पालन की दृष्टि से सबसे उपर्युक्त है;

(3) क्या यह बात सही है कि सरकार द्वारा वर्ष 2010 में 80 हेचरी की मंजूरी दी गयी है लेकिन अभीतक एक भी नहीं खुला है;

(4) यदि उपरोक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार राज्य के मत्स्य पालकों को समुचित साधन उपलब्ध कराकर मछली की उत्पादकता बढ़ाने का विचार रखती है, यदि नहीं, तो क्यों?

राशन की आपूर्ति

26. डॉ० अच्युतानन्द--क्या मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, यह बतलाने की कृपा करेंगे कि--

(1) क्या यह बात सही है कि राज्य में बी०पी०एल० सूची के पुनरीक्षण के बाद ग्रामीण बी०पी०एल० परिवारों की संख्या 1 करोड़ 22 लाख, 55 हजार 110 है;

(2) क्या यह बात सही है कि केन्द्र सरकार द्वारा राज्य में बी०पी०एल० परिवारों की संख्या मात्र 66 लाख के आधार पर राशन एवं किरासन तेल की आपूर्ति की जा रही है;

(3) यदि उपर्युक्त खण्डों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं, तो क्या सरकार शेष 56 लाख 55 हजार 110 बी०पी०एल० परिवारों के लिए राशन एवं किरासन तेल की समुचित आपूर्ति करने का विचार रखती है, यदि नहीं, तो क्यों ?

पटना:
दिनांक 9 दिसम्बर, 2010 (ई०)।

सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा,
सचिव,
बिहार विधान-सभा

बि०स०मु०(एल०ए०), 89-डी०टी०पी०-450